1.00 P.M.

डा. हर्ष वर्धन: सभापति महोदय, आयुष्मान योजना को प्रारंभ करते समय, जो इसका बेसलाइन है, वह 2011 का जो census है, जिसमें socio-economic status के हिसाब से लगभग 10.78 करोड़ परिवार थे, लेकिन भविष्य में our ultimate goal is to make it truly covering all and ensuring that it is truly a universal health coverage. We are working towards that end.

MR. CHAIRMAN: Sanjayji, I hope you are satisfied because the last question is there.

SHRI SANJAY SINGH: Second supplementary, Sir.

MR. CHAIRMAN: The last question is there. If you cooperate, then, we will operate.

MR. CHAIRMAN: Question No.119, Shri Majeed Memon; not present. Q.No. 120, Dr. Satyanarayan Jatiya; not present. …*(Interruptions)*… Are there any supplementaries?

*120. [*प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित थे।*]

'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत सुलभ चिकित्सा उपचार

***120. डा. सत्यनारायण जटिया**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत सभी के लिए चिकित्सा उपचार को सुलभ बनाने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं और वर्ष 2018-19 के दौरान लाभार्थियों और इस योजना पर क्रमश: व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आम आदमी को आकस्मिक तत्काल स्वास्थ्य उपचार सहायता प्रदान करने के लिए क्या-क्या त्वरित उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डा. हर्षवर्धन): (क) से (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आयुष्मान भारत में दो घटक शामिल हैं नामत: (i) आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (सीपीएसी) और (ii) आयुष्मान भारत — प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)।

एबी-एचडब्ल्यूसी के अंतर्गत सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं और इसमें संवर्धनशील, निवारक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या शामिल है। वर्ष 2018-19 के दौरान एबी-एचडब्ल्यूसी के अंतर्गत निर्गत एवं व्यय की गई राशि का राज्य-वार विवरण उपाबंध-I पर है (नीचे देखिए)।

आयुष्मान भारत — प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-बीएमजेएवाई) के अंतर्गत द्वितीयक तथा तृतीयक परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर लगभग 10.74 करोड़ गरीब वंचित परिवारों को 5.00 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक का स्वास्थ्य कवरेज दिया जा रहा है। एबी-पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें से 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने

इसका कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। लाभार्थियों का राज्य-वार विवरण तथा उन्हें आवंटित निधि का राज्य-वार विवरण क्रमश: उपाबंध-II और उपाबंध-III पर है (नीचे देखिए)।

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत, लाभार्थियों को उपचार देने हेतु योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों के उपयोग हेतु 1394 लाभ पैकेज प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें पॉलिट्रामा एवं आपातकालीन प्रबंधन के पैकेज शामिल हैं।

उपाबंध-I

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयुष्मान भारत योजना/स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र (व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या) के अंतर्गत निर्गत एवं व्यय की गई राशि का विवरण

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	
		जारी	व्यय
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.80	2.00
2.	आंध्र प्रदेश	43.51	11.15
3.	अरुणाचल प्रदेश	8.15	3.75
4.	असम	68.67	12.48
5.	बिहार	88.50	27.25
6.	चंडीगढ़	0.71	-
7.	छत्तीसगढ़	36.42	22.94
8.	दादरा और नगर हवेली	0.70	0.05
9.	दमन और दीव	0.43	0.21
10.	दिल्ली	-	-
11.	गोवा	0.79	0.10
12.	गुजरात	44.64	23.62
13.	हरियाणा	18.45	27.10
14.	हिमाचल प्रदेश	16.08	3.40
15.	जम्मू और कश्मीर	32.66	22.70
16.	झारखंड	26.02	19.67

1	2	3	4
17.	कर्नाटक	47.98	27.81
18.	केरल	18.43	16.14
19.	लक्षद्वीप	0.18	-
20.	मध्य प्रदेश	87.74	16.95
21.	महाराष्ट्र	91.27	24.59
22.	मणिपुर	5.44	4.54
23.	मेघालय	8.64	0.66
24.	मिजोरम	4.03	0.28
25.	नागालैंड	5.01	2.29
26.	ओडिशा	48.34	23.66
27.	पुदुचेरी	14.46	0.14
28.	पंजाब	19.69	8.06
29.	राजस्थान	83.70	23.44
30.	सिक्किम	2.16	0.32
31.	तमिलनाडु	56.41	59.51
32.	त्रिपुरा	10.18	0.75
33.	उत्तर प्रदेश	176.10	98.42
34.	उत्तराखंड	19.62	2.91
35.	पश्चिम बंगाल	59.47	2.31
36.	तेलंगाना	46.14	3.31
	कुल	1,191.52	492.51

टिप्पणी: 1. उक्त निर्गत राशि केन्द्रीय सरकारी अनुदान से संबंधित है और इसमें राज्य अंशदान शामिल नहीं है।

2. व्यय में केन्द्रीय निर्गत राशि, राज्य निर्गत राशि से किया गया व्यय एवं वर्ष के प्रारंभ में अव्ययीत शेष राशि शामिल है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु व्यय वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार है, इसलिय यह अनंतिम है।

3. सीपीएचसी में एनआरएचएम तथा एनयूएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के अधीन सीपीएचसी शामिल है।

उपाबंध-II

एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी परिवारों का राज्य-वार विवरण (19.06.2019 तक)

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी परिवार (लाख में)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	0.78
2.	आंध्र प्रदेश*	90.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.89
4.	असम	27.02
5.	बिहार	108.95
6.	चंडीगढ़	0.71
7.	छत्तीसगढ़	41.48
8.	दादरा और नगर हवेली*	0.66
9.	दमन और दीव*	0.45
10.	गोवा	0.37
11.	गुजरात*	70.00
12.	हरियाणा	15.51
13.	हिमाचल प्रदेश	4.80
14.	जम्मू और कश्मीर	6.13
15.	झारखंड*	57.00
16.	कर्नाटक*	115.00
17.	केरल	34.84
18.	लक्षद्वीप	0.01
19.	मध्य प्रदेश*	128.8
20.	महाराष्ट्र	83.63
21.	मणिपुर	2.77
22.	मेघालय*	8.37

क्र.सं.	राज्य	लाभार्थी परिवार (लाख में)
23.	मिजोरम	1.95
24.	नागालैंड	2.33
25.	पुदुचेरी	1.04
26.	पंजाब*	42.00
27.	सिक्किम	0.40
28.	तमिलनाडु*	157.00
29.	त्रिपुरा	4.90
30.	उत्तर प्रदेश	118.04
31.	उत्तराखंड*	19.68
32.	पश्चिम बंगाल	112.00
	कुल	1257.49#

*पीएमजेएवाई का राज्य विस्तार शामिल है।

#एमईसीसी डेटाबेस के अनुसार एबी-पीएमजेएबाई हेतु पात्र 10.74 करोड़ चिह्नित परिवार शामिल हैं।

उपाबंध-III

वर्ष 2018-19 के लिए पीएमजेएवाई के अंतर्गत राज्य-वार निर्गत राशि

क्र. सं.	उन राज्यों के नाम जिन्हें निधि जारी की गई है	राशि (करोड़ ₹ में)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	0.15
2.	आंध्र प्रदेश	182.85
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.31
4.	असम	21.08
5.	बिहार	88.27
6.	चंडीगढ़	0.68
7.	छत्तीसगढ़	217.43

1	2	3
8.	दादरा और नगर हवेली	3.25
9.	दमन और दीव	1.02
10.	गोवा	0.64
11.	गुजरात	77.50
12.	हरियाणा	26.81
13.	हिमाचल प्रदेश	17.18
14.	जम्मू और कश्मीर	20.64
15.	झारखंड*	170.17
16.	कर्नाटक	159.31
17.	केरल	25.00
18.	लक्षद्वीप	0.00
19.	मध्य प्रदेश	72.57
20.	महाराष्ट्र	266.32
21.	मणिपुर	7.18
22.	मेघालय	15.57
23.	मिजोरम	17.48
24.	नागालैंड	4.72
25.	पुदुचेरी	1.52
26.	पंजाब	2.24
27.	सिक्किम	1.03
28.	तमिलनाडु	304.98
29.	त्रिपुरा	12.81
30.	उत्तर प्रदेश	85.01
31.	उत्तराखंड	12.54
32.	पश्चिम बंगाल	31.28
	कुल	1849.55

*120 [*The questioner was absent.*]

Accessible medical treatment under Ayushman Bharat Yojana

†*120. DR. SATYANARAYAN JATIYA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the details of measures taken to make medical treatment accessible to all under the Ayushman Bharat Yojana and the details of beneficiaries and amount spent during the year 2018-19, State-wise; and

(b) the details of quick measures provided under "accidental immediate health treatment assistance" to the common man?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. HARSH VARDHAN): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Ayushman Bharat Yojana comprises two components namely (i) Provision of Comprehensive Primary Healthcare (CPHC) through Ayushman Bharat —Health and Wellness Centres (AB- HWC), and (ii) Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB- PMJAY).

Facilities under AB-HWCs are available to all and include promotive, preventive, and primary health care. The State-wise details of release and expenditure under AB-HWC during the year 2018-19 is at Annexure-I (*See* below).

Under Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), health coverage up to ₹ 5.00 lakh per family per annum is being provided to around 10.74 crore poor, deprived families based on the Socio Economic Caste Census (SECC) for secondary and tertiary care hospitalization. For implementation of AB-PMJAY, Memorandum of Understanding (MoU) has been signed with 33 States/UTs out of which 30 States/UTs have started its implementation. The State-wise details of beneficiaries and funds allotted to the States/UTs are at Annexure-II and Annexure-III respectively (*See* below).

Under AB-PMJAY, 1394 benefit packages have been put in place for usage of hospitals empanelled under the scheme for providing the treatment to the beneficiaries. This includes packages for polytrauma and emergency management.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Annexure-I

Release and Expenditure under Ayushman Bharat Yojana/Health and Wellness Centres (Comprehensive Primary Health Care) for the F.Y. 2018-19

(₹ in crore)

Sl. No.	State	2018-19	
		Release	Expenditure
1	2	3	4
1.	Andaman and Nicobar Islands	0.80	2.00
2.	Andhra Pradesh	43.51	11.15
3.	Arunachal Pradesh	8.15	3.75
4.	Assam	68.67	12.48
5.	Bihar	88.50	27.25
6.	Chandigarh	0.71	_
7.	Chhattisgarh	36.42	22.94
8.	Dadra and Nagar Haveli	0.70	0.05
9.	Daman and Diu	0.43	0.21
10.	Delhi	–	–
11.	Goa	0.79	0.10
12.	Gujarat	44.64	23.62
13.	Haryana	18.45	27.10
14.	Himachal Pradesh	16.08	3.40
15.	Jammu and Kashmir	32.66	22.70
16.	Jharkhand	26.02	19.67
17.	Karnataka	47.98	27.81

1	2	3	4
18.	Kerala	18.43	16.14
19.	Lakshadweep	0.18	–
20.	Madhya Pradesh	87.74	16.95
21.	Maharashtra	91.27	24.59
22.	Manipur	5.44	4.54
23.	Meghalaya	8.64	0.66
24.	Mizoram	4.03	0.28
25.	Nagaland	5.01	2.29
26.	Odisha	48.34	23.66
27.	Puducherry	14.46	0.14
28.	Punjab	19.69	8.06
29.	Rajasthan	83.70	23.44
30.	Sikkim	2.16	0.32
31.	Tamil Nadu	56.41	59.51
32.	Tripura	10.18	0.75
33.	Uttar Pradesh	176.10	98.42
34.	Uttarakhand	19.62	2.91
35.	West Bengal	59.47	2.31
36.	Telangana	46.14	3.31
	TOTAL	1,191.52	492.51

Note: 1. The above releases relate to Central Government Grants and do not include State share contribution.

2. Expenditure includes expenditure against Central Release, State release and unspent balances at the beginning of the year. Expenditure for the F.Y. 2018-19 is as per Financial Management Report (FMR), hence is provisional.

3. CPHC comprises of CPHC under Health System Strengthening under NRHM and NUHM.

Annexure-II

State-wise details for beneficiary families covered under AB-PMJAY (as on 19.06.2019)

Sl. No.	State	Beneficiary families covered (in lakhs)
1	2	3
1.	Andaman and Nicobar Islands*	0.78
2.	Andhra Pradesh*	90.00
3.	Arunachal Pradesh	0.89
4.	Assam	27.02
5.	Bihar	108.95
6.	Chandigarh	0.71
7.	Chhattisgarh	41.46
8.	Dadra and Nagar Haveli*	0.66
9.	Daman and Diu*	0.45
10.	Goa	0.37
11.	Gujarat*	70.00
12.	Haryana	15.51
13.	Himachal Pradesh	4.80
14.	Jammu and Kashmir	6.13
15.	Jharkhand*	57.00
16.	Karnataka*	115.00
17.	Kerala	34.84
18.	Lakshadweep	0.01
19.	Madhya Pradesh*	128.8
20.	Maharashtra	83.63
21.	Manipur	2.77
22.	Meghalaya*	8.37

1	2	3
23.	Mizoram	1.95
24.	Nagaland	2.33
25.	Puducherry	1.04
26.	Punjab*	42.00
27.	Sikkim	0.40
28.	Tamil Nadu*	157.00
29.	Tripura	4.90
30.	Uttar Pradesh	118.04
31.	Uttarakhand*	19.68
32.	West Bengal	112.00
	TOTAL	1257.49 #

*Includes State extensions of PMJAY

#Includes 10.74 crore identified families entitled for AB-PMJAY as per SECC database

Annexure-III

State-wise release made under PM-AY for the year 2018-19

Sl. No.	Name of States to whom funds are released	(Amount in ₹crore)
1	2	3
1.	Andaman and Nicobar Islands	0.15
2.	Andhra Pradesh	182.85
3.	Arunachal Pradesh	2.31
4.	Assam	21.08
5.	Bihar	88.27
6.	Chandigarh	0.68
7.	Chhattisgarh	217.43
8.	Dadra and Nagar Haveli	3.25

1	2	3
9.	Daman and Diu	1.02
10.	Goa	0.64
11.	Gujarat	77.50
12.	Haryana	26.81
13.	Himachal Pradesh	17.18
14.	Jammu and Kashmir	20.64
15.	Jharkhand	170.17
16.	Karnataka	159.31
17.	Kerala	25.00
18.	Lakshadweep	0.00
19.	Madhya Pradesh	72.57
20.	Maharashtra	266.32
21.	Manipur	7.18
22.	Meghalaya	15.57
23.	Mizoram	17.48
24.	Nagaland	4.72
25.	Puducherry	1.52
26.	Punjab	2.24
27.	Sikkim	1.03
28.	Tamil Nadu	304.98
29.	Tripura	12.81
30.	Uttar Pradesh	85.01
31.	Uttarakhand	12.54
32.	West Bengal	31.28
	TOTAL	1849.55

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इतना कहना चाहता हूं कि आयुष्मान योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन जैसा कि हमारे भाई संजय सिंह जी कह रहे थे, इसके parameters बहुत stiff हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इसे थोड़ा नरम करने पर विचार करेंगे, यदि ऐसा होगा, तो उससे बहुत लोगों को फायदा होगा?

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question Hour is over. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Congratulations, Sir. I congratulate you. After a very long time, you have been able to complete. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Identification of environmental risk regarding renewable energy projects

*112. SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: Will the Minister of NEW AND RENEWABLE ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government has identified any environmental risks from renewable energy projects especially wind mills;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any study has been conducted in this regard; and

(d) if so, the details and outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI RAJ KUMAR SINGH): (a) to (d) A study entitled "Development Impact and Sustainable Governance aspects of Renewable Energy Projects" was commissioned by the Ministry of New and Renewable Energy in the year 2013. The major findings of the study are as under:–

(i) The environment and social impacts of wind and solar farms are negligible and renewable projects don' t have long-term irreversible impact on the local environment;

(ii) Renewable energy projects have significant positive social impacts;

(iii) Sufficient environmental and social governance mechanism is in place, and no new changes are required in the legal framework or the governance structures to mitigate or manage the environmental and social impacts from renewable energy.